Finance, has started adjudication proceedings against those officers. I may here assure the House that if any cases of corruption come to our notice we will be very anxious to take very severe action against those found guilty. But I do not think it would be correct to say that the whole of Air India is a pool of corruption. Of course, there has been this unfortunate incident. I am personally very anxious to see that wherever corruption is found it is rooted out.

All-India Roads and Rural Transport Development Programme

+

*1054. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Yashpal Singh:
Shri A. K. Kisku:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Beni Shankar Sharma:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri M. R. Krishna:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration for undertaking an all-India programme for the development of roads and rural transport to the tune of about Rs. 500 crores; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) No Sir. Development of rural roads and rural transport are primarily the responsibility of the State Governments concerned.

(b) Does not arise.

Shri S. C. Samanta: Is it not a fact that the Working Group set up by the Ministry recommended Rs. 740 crores to be spent on development of roads all over India and, if so, whether Rs. 370 crores will be spent by the Centre and Rs. 370 crores by the States?

Shri Bhakt Darshan: Sir, I have not got any exact information with me just now. But the position is that all the proposals are yet to be finalised. Till the Plan allocations are finalised nothing definite can be said.

Shri S. C. Samanta: May I know whether the Nagpur Plan that was in vogue is still continuing? If not, what kind of plan has been taken up and what amount of money will be necessary for what amount of time?

Shri Bhakt Darshan: Sir, the Nagpur Plan has now been replaced by another 20 year plan prepared by the Chief Engineers of various States. That is now in operation. From Plan to Plan and from year to year the allocations are finalised.

Shri S. C. Samanta: What is the amount?

Shri Bhakt Darshan: Sir, I have not got that information just now.

श्री बेणीशंकर शर्मा : अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सड़कों और देहाती परिवहन का मामला स्टेट सब्जेक्ट है और वह अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अतएव क्या वे कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं जिसके अनुसार अगर कोई राज्य सड़कों और देहाती परिवहन के विकास का काम अपने हाथों में ले, तो केन्द्रीय सरकार उस की मदद करेगी।

श्री भक्त दर्शन : जी हां श्रीमन्; चौथी योजना में प्लानिंग कमिशन ने यह प्रस्ताव किया है कि राज्य सरकारें सड़कों के लिए जितने धन की व्यवस्था करें उस का 20 प्रतिशतः ग्रामीण सड़कों के लिए निश्चित किया जाय और उस 20 प्रतिशतः में 40 प्रतिशतः सहायता केन्द्र की ओर से दी जायगी।

Shri M. R. Krishna: May I know whether any discussion has already taken place between the Minister and the State Chief Ministers about the provision of 20 per cent out of the Plan budget of the State Governments for linking the rural roads and, if so, which

are the States which have accepted this suggestion of the Planning Commission?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): Not yet.

Shri S. Kandappan: Along with rural roads I think this question pertains also to the all India roads, I would like to know whether the Government have finalised the plan for the much-promised east-coast road connecting Andhra, Madras and some other States on the eastern side.

Shri Bhakt Darshan: Sir, the East-Coast road has got its own importance, but it is not one of the rural roads.

Shri S. Kandappan: But it will connect the much-neglected rural areas, I would say.

Shri Bhakt Darshan: Sir, if the hon. Member tables a separate question, I will answer it.

Shri Chintamani Panigrahi: The hon. Minister just now referred to the Fourth Plan in which 20 per cent of the allocations would be borne by the State Governments. Which Fourth Plan is he referring to, because, no such Plan has come before the House and we do not know even the outlay of that Plan?

Dr. V. K. R. V. Rao: What my colleague said was that the Planning Commission has suggested that in the Fourth Plan allocations for roads in the State Plans 20 per cent should be reserved for rural roads. If they do, the recommendation of the Planning Commission is that 40 per cent of this 20 per cent will be available as Central grant from the Central allocations.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : केन्द्रीय सरकार के पास क्या कुछ इस प्रकार की शिकायतें भी आई हैं कि राज्यों में प्राय: यह देखा जाता है कि पी० डबलू० डी० के मिनिस्टर जिस जिले के होते हैं उस में सड़कें कुछ अधिक बन जाती हैं बाकी सारा राज्य उपेक्षित रह जाता है तो सारे प्रान्त के साथ बराबर न्याय हो ईस दिशा में या केन्द्रीय सरकार कुछ हस्तक्षेप करेगी या उन की योजनाओं को यहां मंगा कर उन पर अंतिम निर्णय यहां से लिया जायगा ?

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन् ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती; बाकी अगर माननीय सदस्य अपने प्रभाव का इस दिशा में सदुपयोग करें तो सम्भवत: सफलता मिल सकती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हमें आप ने अधिकार कहां दे रक्खा है ? मिनिस्टर तो तो आप हैं ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा चंडीगढ़ यह यूनियन टैरीटैरीज़ हैं । भारत सरकार केन्द्रीय फंड से सड़कों के मामले में इन तीनों टैरीटैरीज़ को कितना कितना रुपया दे रही है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इसके लिये पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री शिव चरण लाल: क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में देहातों में कितनी सड़क बनाने का प्रोग्राम किस हिसाब से है और क्या देहातों से जो पैसा आता है वह पैसा देहातों की सड़कों पर खर्च होता है या वह शहर के विकास में खर्च होता है ? मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री की बात का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री रावत जी ने अपने ही क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया है बाकी सारा आगरा जिला हमारा बर्बाद पड़ा है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं । इस समय स्थिति यह है कि देश में जो लगभग पांच लाख गांव हैं उन में से करीब एक तिहाई गांव ही ऐसे हैं जो बारहमासी सड़कों से जुड़े हुए हैं । इस लिये बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र बचा हुआ है और यदि सब सरकारें मिल कर प्रयत्न करे तो कुछ वर्षों में सफलता मिल सकती है ।

श्री शिव नारायण : शेरशाह ने पांच बरस के अन्दर सारे देश की सड़कों को ठीक किया था। आज स्टेट गवर्नमेंट्स में और सैन्ट्रल गवर्नमेंट में कांफिलक्ट है । आज चूंकि सरकार ने 20 परसेन्ट की बात कही है इस लिये मैं उस को पुराने समय की याद दिलाना चाहता हूं कि अयोध्या से लेकर गोरखपुर और बिहार तक राम जानकी रोड है यह हिस्टारिकल रोड है...

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब सारे इंडिया के बारे में इस तरह से नहीं बतला सकेंगे ।

श्री शिव नारायण : मंत्री महोदय अयोध्या गये थे और मैंने उन से खुद कहा था कि वह सड़क बड़ी हिस्टारिकल सड़क है और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस में मदद कर के उस को बनाये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् अगर माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे तो हम उस को राज्य सरकार के पास भेज देंगे ।

Shri E. K. Nayanar: Even before undertaking the consideration of the Fourth Five-Year Plan the present main road from Mangalore to Madras requires repairs. May I know whether Government has any plan to repair the main road and the only railroad bridge at Beliapattam in Cannanore District or to give aid to the Kerala Government for this?

Mr. Speaker: This has nothing to do with this question.

Shri E. K. Nayanar: It is about repairing the main West Coast Road from Mangalore to Madras.

श्री महाराज सिंह भारती : ग्रामीण सड़कों के सिलसिले में एक योजना पहले से चल रही थी कि एक तिहाई रुपया सड़कें बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार देगी एक तिहाई राज्य सरकार देगी और एक तिहाई में से आधा मिल मालिक देगा और आधा किसान देगा गन्ना मिलों के चारों तरफ सड़कें बनाने के लिये। उस में आम तौर से ऐसा हुआ है कि किसानों ने जो पैसा दे दिया है उस के हिसाब से न तो केन्द्रीय सरकार ने दिया न प्रदेश सरकार ने दिया और न मिल मालिकों ने दिया । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है सड़कें बनाने के लिये क्या उस लक्ष्य में इस योजना के मातहत बनाई जाने वाली सड़कें भी शामिल हैं ? यदि हां, तो उन के लिये आप ने कितना रुपया तय किया है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, ग्रामीण सड़कों के सम्बन्ध में सब से बड़ी बात उन के रख रखाव अर्थात् मेनटेन्स की है । पिछले वर्षों में श्रमदान के द्वारा हजारों क्यों लाखों मील लम्बी सड़कें बनीं थीं पर वह सब समाप्त हो गई । इस लिये मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाये जो इस के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा कि किस प्रकार सड़कों का निर्माण किया जाये और किस प्रकार से उन का रख रखाव किया जाये । राज्य सरकारों से भी इसके बारे में परामर्श किया जायेगा और मुझे आशा है कि जब रिपोर्ट सामने आयेगी तब उस पर अच्छी तरह से कार्य किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र : केन्द्रीय सरकार से बिहार गवर्नमेंट और यू० पी० गवर्नमेंट को एक खत गया था जिस में लिखा था कि एक तिहाई केन्द्रीय सरकार देगी एक तिहाई पैसा राज्य सरकार देगी और एक तिहाई पैसा किसानों और मिल मालिकों से इकट्ठा कर के लिया जाये । और इस पैसे से ग्रामीण सड़कें बनाई जायें । हमारे यहां किसानों से पैसा इकट्ठा कर लिया गया लेकिन न तो मिल मालिकों ने दिया न बिहार गवर्नमेंट ने दिया और न केन्द्रीय सरकार ने दिया । इस के बारे में मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण आना चाहिये ।

Mr. Speaker: You also have learnt this art There is absolutely no point of order Will you kindly sit down? You are a senior Member of the House There is no point of order.

श्री विभूति मिश्र : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि यदि मिनिस्टर साहब गलत जवाब दें तो इस का खुलासा होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार के लेटर की कापी मेरे पास है जिस मे उन्होने कहा था कि एक तिहाई हम देंगे, एक तिहाई बिहार सरकार देगी । किसानो से मुफ्त रुपया इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन सडके आज तक नही बनी है । इस के पीछे क्या बात है यह हम को बतलाया जाना चाहिये ।

Dr. V. K. R. V. Rao *rose*—

Mr Speaker: No, please The point of order is addressed to the Chair and not to the Minister This is where I come into trouble I have to answer it, not the Minister

Shri R. Barua: May I know whether Government has made any assessment of the rural requirements of different States, if so, how much of the require ment Government is going to complete within the next Fourth Five-Year Plan?

Shri Bhakt Darshan: Sir, it is exactly from this point of view that a one-man committee is going to be appointed to look into the matter

Shri D. N. Patodia: Both the Central and the State Governments put together collect about Rs 400 crores in the form of taxation from the road transport industry Will the Government in consultation with the State Governments examine the possibility of earmarking a specific percentage of this tax collection for the development of roads in rural areas?

Shri Bhakt Darshan: Sir, I think, this very question was put to the Deputy Prime Minister and Finance Minister at Bombay recently and he has rejected it outright, as it is not practicable

श्री गंगा रेड्डी : मै जानना चाहता हूं कि बीस सालो का जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था उस मे से अब तक कितने साल खत्म हो गये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जो पहला बीस साल का प्रोग्राम था, वह सन् 1941 से ले कर 1961 तक था । उस के बाद दूसरे बीस साल का प्रोग्राम चल रहा है ।

Shri Gadilingana Gowd: May I know if it is a fact that the Central Government has agreed to bear all the expenditure on the construction of inter-State bridges, if so, have Mysore and Andhra Governments asked for the construction of a bridge on Tungbhadra River near Madhavaram Mantrayalam?

Shri Bhakt Darshan: Sir, about the second part of the question I want notice About the first part of the question, there is a scheme, but, under that scheme, all roads or bridges cannot be undertaken, only a few selected ones can be undertaken

श्री द्वा० ना० तिवारी : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष बीत रहे है । आपने कहा है कि 20 परसेन्ट से 40 परसेन्ट अनुदान आप देंगे । मै जाना चाहता हू कि इन दो वर्षों मे आप ने कुल कितना अनुदान प्रदेशो को दिया है और किन किन प्रदेशों को कितना कितना ?

श्री भक्त दर्शन श्रीमन् माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि इन दो वर्षों मे एक भी पैसा नये कामो के लिये नही दिया गया । इस लिये यह प्रश्न नही उठता ।

श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या यह सच नही है कि वर्तमान सरकार जो सडके बनवा रही है उन के पीछे आर्थिक दृष्टिकोण प्रधान है और स्टेट गवर्नमेंट्स इस बात को ध्यान मे रख कर सडके बनवाती हैं ? परन्तु भारतवर्ष मे ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आर्थिक दृष्टिकोण से सडकें बनवाना लाभदायक नही । लेकिन भारतवर्ष मे जो ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर कि आदिवासी रहते

हैं, उन जंगलों मे अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटरों के दर्शन नहीं किये हैं, रेलों के दर्शन नही किये हैं। उन क्षेत्रों को भारतवर्ष की आम जनता के साथ मिलाने के लिये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां सडके बनाने की ओर विशेष ध्यान देने का विचार कर रही है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इसी दृष्टिकोण से प्लेनिंग कमिशन ने यह योजना रक्खी है। जब चतुर्थ पचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप आ जायेगा, तब शायद इन मामले मे कुछ प्रगति हो सकेगी।

श्रीमती जयाबेन शाह : जहा बहुत सी स्टेट्स नागपुर प्लैन से बहुत पीछे है वहा कई स्टेट्स ऐसी भी हैं जो कि नागपुर प्लैन से बहुत आगे बढ गई हैं। मैं जानना चाहती हू कि दोनो के बीच मे रैशनलाजेइशन लाने के लिये जो पिछडी स्टेट्स हैं क्या उन के लिये कोई खास कारंवाई होने वाली है ?

श्री भक्त दर्शन . श्रीमन् जैसा माननीया सदस्या ने कहा है कुछ राज्य सरकारे नागपुर प्लैन से भी आगे बढ गई हैं। लेकिन उन को पीछे लाने का कोई इरादा नही है। हा, जो पीछे रह गई हैं, उन्हे अवश्य आगे बढाने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री लखण लाल कपूर माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि सडको पर जितना रुपया खर्च होगा प्लैनिंग कमिशन उस मे से 20 परसेंट रुपया ग्रामीण सड़को के ऊपर खर्च करने की योजना बनाई है। क्या मंत्री महोदय इस बात को महसूस करते हैं कि ग्रामीण सडकों पर खर्च करने के लिये यह बहुत कम रुपया है और इस के लिये क्या उन्होने कहा है कि ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिये ?

श्री भक्त दर्शन श्रीमन् यह जो 20 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है, यह तो न्यूनतम है। यदि इस से अधिक राज्य सरकारे खर्च करना चाहे तो हम उस का स्वागत करेंगे।

Re-opening of Suez Canal

+

***1055. Shri Kameshwar Singh:**
Shri C. C. Desai:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether normal crossing of the Suez Canal has been resumed and, if not, what is the obstacle;

(b) when will such an obstacle be removed,

(c) whether the ships carrying cargo for India are held up or are making the journey round the Cape of Good Hope, and

(d) if so, what will be the additional cost to India, by the adoption of this lengthy route?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) and (b). The Suez Canal remains closed because of the sunken ships and the aftermath of hostilities The U A R Government are not willing to remove the sunken ships as long as the Israeli troops continue to occupy the east bank of the Canal

(c) The U S tanker 'Observer' carrying 27 400 tons of Milo for India is held up in the Suez Canal Ships carrying cargo for India are now using the route *via* the Cape of Good Hope

(d) On preliminary estimates the total additional freight bill on account of the diversion *via* the Cape of Good Hope is likely to be of the order of Rs 35 05 crores per annum, assuming that imports and exports continue to remain as at present

Mr. Speaker: Question No 1064 can also be linked up with this

Dr. V. K. R. V. Rao: That is addressed to the Minister of Food and Agriculture

Mr. Speaker: That is also about Suez Canal Anyway, it is all right

श्री कामेश्वर सिंह : क्या मंत्री महोदय ने यहा से कोई अफसर या कोई दूसरा व्यक्ति स्वेज एरिया में भेजा है, जो वहां पर जा कर